भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1856
दिनांक 14 दिसम्बर, 2023

प्राकृतिक गैस का भण्डार

1856. सुश्री देबाश्री चौधरी:
श्रीमती पूनम महाजनः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के प्रत्येक क्षेत्र में कुल प्राकृतिक गैस भंडार के संबंध में कोई सर्वेक्षण/अन्वेषण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण किस अवधि में किया गया था और प्राकृतिक गैस का कुल कितना भंडार था;

(ग) क्या किसी सर्वेक्षण से यह पता चला है कि भारत में प्राकृतिक गैस की वार्षिक खपत की तुलना में भारत में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को कम करने के लिए प्राकृतिक गैस भंडार का पूर्ण दोहन करने की कोई नीति है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग) हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एक सतत कार्यकलाप है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भूकंपीय डेटा अधिग्रहण, प्रसंस्करण, व्याख्या, कूप वेधन और अन्य अन्वेषण सम्बन्धी कार्यकलाप (जैसे एयरबोर्न ग्रेविटी ग्रेडियोमेट्री, आदि) शामिल हैं। हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी), नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी), एनईएलपी-पूर्व/नामांकन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी), ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) जैसी राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज) और अन्य निजी प्रचालकों, जिनके साथ भारत सरकार ने राजस्व हिस्सेदारी संविदा (आरएससीज) और उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससीज) पर हस्ताक्षर किए हैं, द्वारा विभिन्न अन्वेषण सम्बन्धी कार्यकलाप किए जाते हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने निम्नलिखित सर्वेक्षण परियोजनाएँ शुरू की हैं:

सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यकलाप	अवधि
हाइड्रोकार्बन पुनर्मूल्यांकन सर्वेक्षण	सितंबर 2015- नवंबर 2017
राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम	वर्ष 2017-2018 को शुरू हुआ और दिनाँक 31.03.2022 को पूरा हुआ
एयरबोर्न जियोफिजीकल सर्वेक्षण	दिनाँक 27.05.2023 को शुरू हुआ और अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है
डीप अंडमान ऑफशोर परियोजना	वर्ष 2021-22 में शुरू हुआ और दिनाँक 31.03.2023 को पूरा हुआ
ईईजेड तक तलछटी बेसिन का मूल्यांकन	वित्त वर्ष 2022-23 में शुरू हुआ और अधिग्रहण पूरा हो गया, प्रसंस्करण और व्याख्या अभी प्रक्रियाधीन है।

अन्वेषण सम्बन्धी कार्यकलापों के परिणामस्वरूप दिनाँक 01.04.2023 की स्थिति के अनुसार देश में लगभग 1829.56 बीसीएम गैस की एस्टीमेटेड अल्टीमेट रिकवरी (ईयूआर) सहित प्रारंभ में लगभग 3952.68 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) इन-प्लेस गैस (2पी) प्राप्त है। स्थल-वार विवरण निम्नानुसार हैं:

दिनाँक 01.04.2023 की स्थिति के अनुसार प्राकृतिक गैस भंडार की स्थल-वार स्थिति (अनंतिम)			
स्थल	**2पी इन प्लेस गैस (बीसीएम)**	**2पी ईयूआर गैस (बीसीएम)**	**2पी रिजर्व्स गैस (बीसीएम)**
ऑफशोर	2195.50	1124.83	360.17
ऑनलैण्ड	1757.18	704.73	290.46
देश का कुल योग	**3952.68**	**1829.56**	**650.63**

स्रोत: हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच)

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्राकृतिक गैस की वार्षिक खपत 59.969 बीसीएम थी।

(घ) एवं (ङ) सरकार ने प्राकृतिक गैस भंडार का दोहन करने के लिए हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति में सुधार, उन्नत तेल निकासी (ईओआर) को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की नीति, कोयला खनन पट्टे के अन्तर्गत क्षेत्रों से कोल बेड मीथेन (सीबीएम) का अन्वेषण और दोहन के लिए नीतिगत ढ़ाँचा और सीबीएम का शीघ्र मुद्रीकरण जैसे विभिन्न नीतिगत पहल की हैं ताकि पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को कम किया जा सके। अन्वेषण के अन्तर्गत शुद्ध भौगोलिक क्षेत्र को 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर (एसकेएम) से बढ़ाकर 5 लाख एसकेएम करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के 99% 'नो-गो' क्षेत्र को खोल दिया है।

इसके अलावा, आयात को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करने के निमित्त सरकार ने एक बहुउ ेयीय कार्यनीति अपनाई है जिसमें तेल और गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाना, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण सम्बन्धी उपायों को बढ़ावा देना, माँग प्रतिस्थापन पर जोर देना, जैव ईंधन और अन्य वैकल्पिक ईंधन/नवीकरणीय को बढ़ावा देना, आयातित कच्चे तेल पर देश की तेल निर्भरता को कम करने के लिए ईवी चार्जिंग सुविधाएँ और रिफाइनरी प्रक्रिया में सुधार करना शामिल है।

***